

दिनांक 17.08.2017 को उपायुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में आहूत जिला समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

**उपस्थिति :- पंजी में संधारित**

उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। मनरेगा योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है :-

### **प्रधानमंत्री आवास योजना**

प्रधानमंत्री आवास योजना का समीक्षा के क्रम में प्रखण्डवार निम्नलिखित निदेश दिया गया

1. समीक्षा के क्रम में बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों में गृह प्रवेश का लक्ष्य दिया गया है। इसलिए लिए सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सितम्बर 2017 तक शत-प्रतिशत आवासों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. देवरी प्रखण्ड का समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक एक भी योजना पूर्ण नहीं हुआ है तथा Geo tag की स्थिति भी खराब है एवं 911 लाभुकों को प्रथम किस्त दिया गया है, लेकिन 4<sup>th</sup> Installment मात्र 75 लाभुकों को ही दिया गया है। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी द्वारा बताया गया कि 150 आवासों को पूर्ण कराने में समस्या आ रही है एवं 850 आवास अगस्त 2017 तक पूर्ण हो जाएगा। प्रखण्डवार समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी को निम्नलिखित निदेश दिया गया -
  - i. जनसेवक, ग्राम रोजगार सेवक एवं स्वयं सेवक को लगाकर आवासों का भौतिक सत्यापन करावें तथा प्रत्येक चार दिनों में उनके साथ समीक्षा करें तथा मुखिया से बात कर अश्वस्थ हो लें कि जनसेवक, ग्राम रोजगार सेवक एवं स्वयं सेवक क्षेत्र में जा रहे हैं या नहीं।
  - ii. Geo tag एवं आवास निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित कर ग्राम रोजगार सेवक को दें।
  - iii. समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी द्वारा बताया गया कि 800 से अधिक आवास का कार्य Plinth Level से ऊपर तक हो गया है। निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी लगातार समीक्षा करें तथा जितने योजनाओं में Plinth Level तक कार्य हो गया है उन योजनाओं में 10 दिनों में लिंटल तक कार्य हो जाना चाहिए।
  - iv. समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि Geo tag करने हेतु जिनको लगाना है लागावें और अविलंब ससमय शत-प्रतिशत Geo tag करावें एवं उनको Incentive का भुगतान करें। मनरेगा सेल को निदेश दिया गया कि

गावां, देवरी, बेगाबाद के अलावें जिन प्रखण्डों की स्थिति दयनीय है उन प्रखण्डों का भ्रमण करें।

3. बिरनी प्रखण्ड का समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिरनी प्रखण्ड में सबसे कम 4<sup>th</sup> Installment दिया गया है। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी द्वारा बताया गया कि नाजीर नया है, इसलिए समस्या हो रहा है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी को कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।
4. जमुआ प्रखण्ड का समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमुआ को कार्य में तेजी लाते हुए ससमय आवासों को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।
5. पीरटॉड प्रखण्ड का समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पीरटॉड द्वारा बताया गया कि 1180 योजना में Plinth Level तक कार्य हो गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पीरटॉड को कार्य की गति बनाएँ रखने एवं ससमय किस्त का भुगतान करने का निदेश दिया गया।
6. प्रधानमंत्री आवास योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 का समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अगस्त 2017 तक Geo tag कराकर प्रथम किस्त का भुगतान कर दें।

### इन्दिरा आवास योजना

प्रखण्डवार लंबित इन्दिरा आवास योजना की स्थिति निम्नवत् है -

### INDIRA AAWAAS YOJANA

GIRIDIH		FY - 2011-2015					17-8-17			
#	Blocks	Target	Completed		Achievement	Pending		Pending %		
			26-7-17	17-8-17	26 July to 17 August	26-7-17	17-8-17	26-7-17	17-8-17	
1	Bagodar	882	596	596	0	286	286	32%	32%	
2	Bengabad	1918	1007	1022	15	911	896	47%	47%	
3	Birni	894	696	699	3	198	195	22%	22%	
4	Deori	2614	1317	1370	53	1297	1244	50%	48%	
5	Dhanwar	1374	998	1001	3	376	373	27%	27%	
6	Dumri	2578	1953	1970	17	625	608	24%	24%	
7	Gandey	2367	1591	1597	6	776	770	33%	33%	
8	Gawan	1122	841	841	0	281	281	25%	25%	
9	Giridih	2726	1907	1907	0	819	819	30%	30%	
10	Jamua	2081	1490	1523	33	591	558	28%	27%	
11	Pirtand	2777	1791	1831	40	986	946	36%	34%	
12	Suriya	859	726	726	0	133	133	15%	15%	
13	Tisri	1806	940	979	39	866	827	48%	46%	
	Total	23998	15853	16062	209	8145	7936	34%	33%	

समीक्षा के क्रम में तिसरी एवं बैगाबाद प्रखण्ड में सबसे अधिक क्रमशः 48% एवं 47% इन्दिरा आवास लंबित पाया गया। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैगाबाद द्वारा बताया गया कि कुछ क्षेत्र में लोग शराब पिये रहते हैं और आवास बनाने के लिए बोलने पर बोलते हैं कि नहीं बनाएँगे। इसी क्रम में उप विकास आयुक्त, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि सर्वे कराया गया है उसमें कुछ लाभुक ऐसे भी हैं, जो किस्त का इन्तेजार कर रहे हैं। समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित निदेश दिया गया -

1. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन लाभुकों के द्वारा आवास बनाने में अभिरुचि नहीं लिया जा रहा है, उन पर प्राथमिकी दर्ज करें।
2. निदेशक, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह को देवरी प्रखण्ड के खटौरी, तिलकडीह एवं खरखरी पंचायत का जाँच करने का निदेश दिया गया। निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि उप विकास आयुक्त महोदया के द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड की जाँच हेतु जाँच दल का गठन किया गया है। उक्त जाँच दल द्वारा जाँच करा ली जाएगी।
3. इन्दिरा आवास के लाभुकों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा किस्त की राशि नहीं दिये जाने पर काफी रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि जिन प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा किस्त की राशि नहीं दिया गया है उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू करें।

#### बाबा भीम राव अम्बेडकर आवास योजना

समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को लाभुकों का रजिस्ट्रेशन कार्य शुरू कराने का निदेश दिया गया तथा अगस्त 2017 तक Geo tag कराकर प्रथम किस्त का भुगतान कर दें।

#### KYC

KYC का समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले में 500 KYC लंबित है। प्रति प्रखण्ड लगभग 40 से 50 है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया से समन्वय स्थापित कर शत-प्रतिशत KYC करावें।

#### मनरेगा

मनरेगा योजना का समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित निदेश दिया गया -

1. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि किसी भी परिस्थिति में Zero Muster Roll नहीं होना चाहिए।
2. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ससमय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सप्ताह में दो से तीन दिन मुखिया को प्रखण्ड में बुलाकर भुगतान करवाने का निदेश दिया गया।

3. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने एवं प्रति ग्राम कम से कम पाँच योजना शुरू कराने का निदेश दिया गया। साथ ही प्रति पंचायत 50-50 शौचालय और नाडेफ/वर्मी कम्पोस्ट की योजना शुरू कराने का निदेश दिया गया।
4. शौचालय निर्माण की योजना में सामग्री का भुगतान लाभुक को करेंगे।
5. समीक्षा के कम में बताया गया कि कुल 8336 शौचालय मनरेगा से जिले में स्वीकृत हुआ है। शौचालय निर्माण कार्य का स्तर बढ़ाने और स्वीकृत सभी शौचालयों को अविलंब पूर्ण करवाने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।

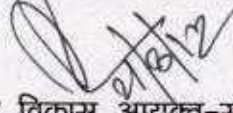
अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

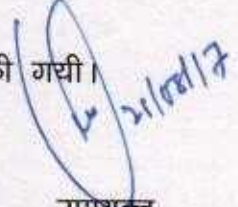
परियोजना पदाधिकारी,  
डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।

उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
गिरिडीह।

उपायुक्त,  
गिरिडीह।

  
19/8/17



  
21/08/17

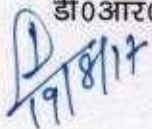
ज्ञापांक 2317 /अभि0, गिरिडीह, दिनांक 22 अगस्त, 2017

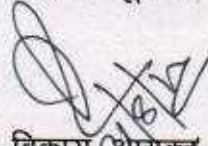
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद्, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेबसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, अररी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

परियोजना पदाधिकारी,  
डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।

उप विकास (आयुक्त)-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
गिरिडीह।

उपायुक्त,  
गिरिडीह।

  
19/8/17



  
21/08/17